खंड १ नंबर १ जनवरी २०१७

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य

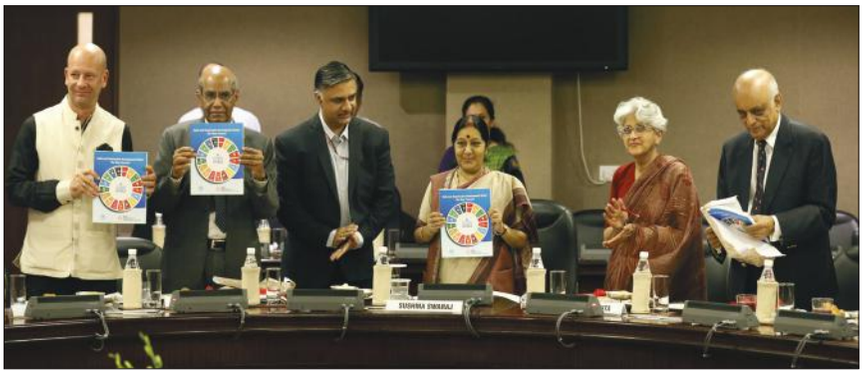

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आरआईएस की *'भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : आगे की राह'* शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन करती हुईं। साथ में हैं (बाएं से दाएं) संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के निवासी (स्थानीय) प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव, आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता और आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री एस.टी. देवारे।

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 7 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में *'भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : आगे की राह'* शीर्षक आरआईएस प्रकाशन का विमोचन किया। इस पुस्तक में 19 विस्तृत लेख हैं जो टिकाऊ विकास की समस्त श्रेणियों तथा दो अन्य विषय, वित्त और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हैं।

इस पुस्तक के लिए अपने संदेश में माननीया विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत टिकाऊ विकास के लिए 2030 एजेंडे को उच्च प्राथमिकता देता है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2015 में सर्वसम्मति से अपनाया था और जो मानव जाति की खुशहाली एवं प्रगति के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। मैं उन 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समग्र कार्यान्वयन के लिए भारत की मजबूत

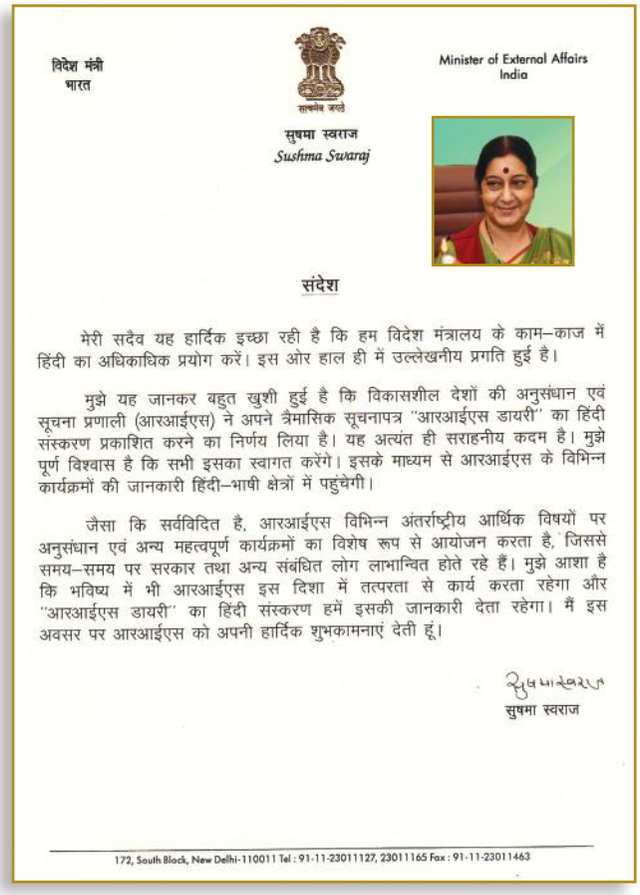

विदेश मंत्री
भारत

सत्यमेव जयते

Minister of External Affairs
India

सुषमा स्वराज
Sushma Swaraj

संदेश

मेरी सदैव यह हार्दिक इच्छा रही है कि हम विदेश मंत्रालय के काम–काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। इस ओर हाल ही में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने अपने त्रैमासिक सूचनापत्र "आरआईएस डायरी" का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह अत्यंत ही सराहनीय कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी इसका स्वागत करेंगे। इसके माध्यम से आरआईएस के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी हिंदी–भाषी क्षेत्रों में पहुंचेगी।

जैसा कि सर्वविदित है, आरआईएस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विषयों पर अनुसंधान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विशेष रूप से आयोजन करता है, जिससे समय–समय पर सरकार तथा अन्य संबंधित लोग लाभान्वित होते रहे हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आरआईएस इस दिशा में तत्परता से कार्य करता रहेगा और "आरआईएस डायरी" का हिंदी संस्करण हमें इसकी जानकारी देता रहेगा। मैं इस अवसर पर आरआईएस को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

सुषमा स्वराज

172, South Block, New Delhi-110011 Tel : 91-11-23011127, 23011165 Fax : 91-11-23011463

प्रतिबद्धता को रेखांकित करना चाहती हूं जो हमारे खुद के प्रमुख कार्यक्रम और प्राथमिकताओं को काफी हद तक प्रतिबिंबित करते हैं। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक (रेज़िडेंट कोआर्डिनेटर) एवं भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव और विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस प्रकाशन में अहम योगदान करने वाले लेखकगण भी इसके विमोचन के दौरान उपस्थित थे।

माननीया विदेश मंत्री नें यह बात भी रेखांकित की है कि यह पुस्तक (वाल्यूम) 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में जुटे लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होगी और केंद्र एवं राज्य स्तरों

पर प्रभावपूर्ण नीतिगत सामंजस्य विकसित करने में मददगार होगी। माननीया मंत्री की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आरआईएस की इस पुस्तक की प्रतियां भारत में लोकसभा और राज्य सभा दोनों के ही सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध कराई गई हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस अवसर पर कहा, 'प्रगति, समावेश और स्थायित्व के कई क्षेत्रों में एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु भारत ने पहले ही खुद के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिए हैं।' उन्होंने कहा, 'इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ–साथ एसडीजी के साथ सामंजस्य बैठाने में भी राज्य सरकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी बदौलत एसडीजी की प्राप्ति के लिए सभी सामाजिक और आर्थिक मानकों को कारगर ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एसडीजी की प्राप्ति के प्रति भारत के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने में नीति आयोग सबसे आगे रहा है। आरआईएस इस संदर्भ में नीति आयोग, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एसडीजी एजेंडे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपसी सामंजस्य वाला नीतिगत ढांचा विकसित करने हेतु परामर्श संबंधी बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन करता रहा है।

आरआईएस की 'भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्यः आगे की राह' शीर्षक वाली पुस्तक में अहम योगदान करने वाले महानुभावों के साथ माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने कहा, 'आरआईएस टिकाऊ विकास लक्ष्यों के एजेंडे के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित की जाने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचर्चाओं में व्यापक योगदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और इसने अनेकानेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंत्रणाओं का आयोजन किया है।'

संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव ने भी भारत में एसडीजी की प्राप्ति हेतु पूरी सक्रियता के साथ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए आरआईएस और नीति आयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने एसडीजी के लिए भारत की प्रतिबद्ध ता दोहराई।

ब्रिक्स समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजेंडे को व्यापक करेगा : शशि थरूर

भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और आरआईएस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 3–4 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम का आयोजन किया था। यह भारत की मेजबानी में उसकी अध्यक्षता के दौरान अक्टूबर 2016 में गोवा में आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले महत्वपूर्ण ट्रैक–2 श्रेणी का आयोजन था। माननीय सांसद एवं विदेश मामलों पर स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एवं एफआईडीसी की अध्यक्ष सुश्री अनुराधा चिनॉय ने स्वागत भाषण दिए।

ब्रिक्स देशों एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो दिवसीय विचार–विमर्श में भाग लिया,

माननीय सांसद एवं विदेश मामलों पर स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर ब्रिक्स सिविल फोरम में उद्घाटन भाषण देते हुए।

जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, गरीबी, इत्यादि के मुख्य सामाजिक क्षेत्रों के साथ–साथ टिकाऊ विकास, शहरीकरण एवं वित्तीय मुद्दों पर भी सिविल सोसायटी और निर्णय लेने वालों के बीच एक रचनात्मक संवाद सुनिश्चित करना था।

डॉ. शशि थरूर ने फोरम का उद्घाटन करते हुए कहा, 'ब्रिक्स एक वैकल्पिक फोरम है जो दुनिया की नीतियों को नया स्वरूप प्रदान करने वाले प्रभावशाली समुदायों के सामने मजबूती से डटा हुआ है। तीन ट्रिलियन की आबादी वाले ब्रिक्स देश दुनिया की आबादी के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 प्रतिशत योगदान देते हैं और अब ये

पेज 12 पर जारी...

ब्रिक्स आर्थिक मंच

आरआईएस ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 13 एवं 14 अक्टूबर, 2016 को गोवा में सफलतापूर्वक प्रथम ब्रिक्स आर्थिक मंच का आयोजन किया। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ–साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं वरिष्ठ बैंकरों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री समीर खरे ने बैठक का संदर्भ निर्धारित किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक (भारत) डॉ. सुबीर गोकर्ण ने उद्घाटन भाषण दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उद्घाटन सत्र के बाद ब्रिक्स तथा बहुपक्षीय संस्थानों, ब्रिक्स एवं विकास के लिए वित्त पोषण, ब्रिक्स एवं अभिनव अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स एवं वित्तीय बाजारों पर चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। ब्रिक्स

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ब्रिक्स आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए।

के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ वैश्विक मानक तय करने, नीतिगत समन्वय एवं संकट प्रबंधन पर एक पैनल परिचर्चा और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों के साथ टिकाऊ विकास के लिए सहयोग पर एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ एक विशेष संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री शक्तिकांत दास भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रतिभागियों ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का कार्य सुनिश्चित करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आईओआरए ब्लू इकोनॉमी संवाद

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 4–5 नवंबर 2016 को 'हिंद महासागर में ब्लू इकोनॉमी की आर्थिक संभावनाओं और वाणिज्यीकरण के पहलुओं' पर आईओआरए ब्लू इकोनॉमी संवाद का आयोजन किया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। नई दिल्ली स्थित विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के महानिदेशक राजदूत नलिन सूरी और आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की।

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने उद्घाटन भाषण दिया।

ब्लू इकोनॉमी संवाद के दौरान आईओआरए क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) की आर्थिक संभावनाओं को लेकर पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबुद्ध परिचर्चाओं को प्रोत्साहित किया गया। नवीकरणीय समुद्री

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) आईओआरए के नीतिगत संक्षिप्त वृतान्त *'आईओआरए में मत्स्य पालन क्षेत्र : क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी की संचालक शक्ति'* का विमोचन करते हुए। साथ में हैं (बाएं से दाएं) प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, राजदूत सुधीर देवारे, अध्यक्ष, अनुसंधान सलाहकार परिषद, आरआईएस, और सुश्री रेणु पाल, संयुक्त सचिव (आईओआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।

ऊर्जा, मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में एवं अपतटीय खनन, तटीय पर्यटन एवं शहरीकरण और समुद्री एवं सामरिक आयाम इन पांच क्षेत्रों में शामिल हैं।

अधिक जानकारी आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं : www.ris.org.in

भारत–जापान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए निर्यात के मार्ग की बाधाओं को दूर करने की जरूरत : निर्मला सीतारमण

आरआईएस में स्थापित एआईसी ने नई दिल्ली में 6 अक्टूबर 2016 में भारत–जापान सीईपीए के तहत भारत से जापान को निर्यात के संवर्धन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार की माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा *'भारत–जापान सीईपीएः एक मूल्यांकन'* के शीर्षक वाली आरआईएस–एआईसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने इस रिपोर्ट के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों का व्यापक विवेचन किया गया है। भारत सरकार के विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर और जापानी दूतावास में राजदूत (असाधारण एवं

भारत सरकार की माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमण *भारत–जापान सीईपीए* पर आरआईएस–एआईसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हुई।

पूर्णाधिकारी) महामहिम श्री केंजी हीरामत्सु ने भी विशेष भाषण दिए। संगोष्ठी के दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। भारत से जापान को होने वाले कपड़ा और परिधान निर्यात को मूल्य एवं मात्रा के लिहाज से बढ़ाना, भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना, वर्ष 2020 तक जेनेरिक के अधिकाधिक उपयोग की दिशा में जापान के फैसले से उत्पन्न होने वाले कारोबारी अवसर – भारतीय कंपनियां किस तरह से अनुकूल कदम उठा सकती हैं तथा तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में आईटी एवं इससे संबद्ध सेवाओं के व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देना किस प्रकार संभव है।

बिम्सटेक और आईबीएसए रिपोर्टों का विमोचन

आरआईएस ने दो प्रमुख प्रकाशन प्रकाशित किए, जिनमें बिम्सटेक और आईबीएसए से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी गई है। *'बिम्सटेक – आगे की राह और आईबीएसए – विकास, लोकतंत्र और स्थायित्व के लिए ट्रिनिटी'* शीर्षक युक्त दो रिपोर्टों को भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा 9 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में विमोचन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने आरंभिक भाषण दिया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक ए. डिमरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आईबीएसए की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) के इतिहास में आईबीएसए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में डटा हुआ है। आईबीएसए के सदस्य देश बहुपक्षवाद एवं शांति की वकालत करते हैं, संप्रभुता के

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) *'बिम्सटेक – आगे की राह*, और *'आईबीएसए – विकास, लोकतंत्र और स्थायित्व के लिए ट्रिनिटी'* के शीर्षक वाली दो रिपोर्टों को पेश करते हुए।

लिए सम्मान को बढ़ावा देते हैं, लोगों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, विकासशील एवं विकसित देशों के बीच व्यापार और आर्थिक पहलुओं को अपना भरपूर समर्थन देते हैं। इसी तरह, बिम्सटेक की रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि कई क्षेत्रों में प्रत्येक देश की क्षमताएं बिम्सटेक समूह के सदस्य देशों के बीच साझा करने और सीखने का एक स्रोत साबित हो सकती हैं। 'बंगाल की खाड़ी आर्थिक समुदाय' के संभावित गठन के लिहाज से बिम्सटेक एक महत्वपूर्ण निर्माण ब्लॉक है।

भारत में प्रौद्योगिकी और विज्ञान नीति को नया स्वरूप प्रदान करना

आरआईएस ने 15 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी के हाथों *'ए लाइफटाइम ऑफ मॉउल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस पॉलिसी इन इंडिया'* नामक पुस्तक के विमोचन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माननीय उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक (वॉल्यूम) का विमोचन किया और इसे प्रो. अशोक पार्थसारथी को पेश किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने यह बात रेखांकित की कि हमारे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियां तैयार करते समय जिस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा की जाती रही है वह हमारे विश्वविद्यालयों का विकास, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान की अहम आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) नीतियां तैयार करते समय विश्वविद्यालयों की उस केंद्रीय भूमिका को अवश्य ही ध्यान में रखा जाएगा जो वे राष्ट्र के नवाचार और नवविचार केंद्रों के रूप में निभा सकते हैं। चेन्नई स्थित एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के एमेरिटस अध्यक्ष प्रो. एम एस स्वामीनाथन, बंगलुरू स्थित उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केंद्र के एमेरिटस प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा (अनुपस्थिति में), नई दिल्ली स्थित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. मालती गोयल, प्रो. अशोक पार्थसारथी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस पुस्तक को संपादित किया है और इसमें प्रख्यात हस्तियों ने भी योगदान दिया है।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग

आरआईएस में स्थापित एआईसी, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) और नेवल वार कॉलेज (एनडब्ल्यूसी) के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेने वाले देशों के लिए 4–5 नवंबर, 2016 को गोवा में 'समुद्री सुरक्षा और सहयोग' पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ईएएस सम्मेलन का आयोजन किया। सभी ईएएस देशों ने सम्मेलन के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सुश्री प्रीति सरन ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने आरंभिक भाषण दिया। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के निदेशक डॉ. विजय सखूजा ने विशेष भाषण दिया। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल) सुश्री पूजा कपूर ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। गोवा स्थित एनडब्ल्यूसी में कमांडेंट रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, एनएम, ने विशेष भाषण दिया।

समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग और समुद्री बहुपक्षवाद पर गहराई से बहस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मेलन को इन पांच सत्रों में विभाजित किया गया: एशिया–प्रशांत में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे, एशिया–प्रशांत में समुद्री संरक्षा के मुद्दे, समुद्री बहुपक्षवाद: एशिया– प्रशांत के लिए अवसर, चुनौतियां और संभावनाएं, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संरक्षण, आगे की राह। इन सभी विषयों पर सम्मेलन में चर्चाएं और विश्लेषण किया गया और फिर उन विभिन्न अंशों को आपस में जोड़ा गया जो समुद्री क्षेत्र के लिए ईएएस में भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। एनएमएफ के निदेशक डॉ. विजय सखूजा ने समापन सत्र को संबोधित किया। एनडब्ल्यूसी में डिप्टी कमांडेंट कमोडोर अशोक राय और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ग्रुप फोटो : 'समुद्री सुरक्षा और सहयोग' पर दूसरे ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रियर एडमिरल सुरेश मेहता।

आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर ईएएस सम्मेलन

ग्रुप फोटो : आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ श्री किरेन रिजिजू, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, सुश्री प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

आरआईएस में स्थापित एआईसी, गृह मंत्रालय (एमएचए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भूकंप जोखिम न्यूनीकरण केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेने वाले देशों के लिए 2 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में 'आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग पर ईएएस सम्मेलन' का आयोजन किया। सभी ईएएस देशों ने सम्मेलन के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इस एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) में माननीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सुश्री प्रीति सरन ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने आरंभिक भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक प्रो. संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षेत्रीय सहयोग पर गहराई से बहस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मेलन को दो सत्रों में विभाजित किया गया था: (1) आपदा जोखिम न्यूनीकरण, टिकाऊ विकास लक्ष्य एवं क्षेत्रीय सहयोग और (2) आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग। सम्मेलन में चर्चाएं की गईं, विश्लेषण किया गया और फिर उन विभिन्न अंशों (कंपोनेंट) को आपस में जोड़ा गया जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर ईएएस में भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एजेंडा 2030 पर सत्रः यूरोप और भारत में कार्यान्वयन

यूरोपीय आयोग के मुख्यालय ब्रुसेल्स से आए यूरोपीय संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 'एजेंडा 2030: यूरोप और भारत में कार्यान्वयन' विषय पर एक परस्पर संवादात्मक सत्र 9 दिसंबर, 2016 को आरआईएस द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में श्री गुस्तावो मार्टिन प्रादा, निदेशक, विकास नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, श्री पेड्रो हेनरिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिकारी, नीति और सामंजस्य (विकास), श्री माइकल जॉन एलिस, महानिदेशालय, नीति अधिकारी, नीति और सामंजस्य (विकास) और डॉ. जोहान हेस्से, काउंसलर, भारत के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सहयोग प्रमुख के साथ–साथ

आरआईएस में परस्पर संवादात्मक सत्र के दौरान यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

भारत के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल की वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रेणुका श्रीनिवासन भी शामिल थीं। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर ने परस्पर संवादात्मक सत्र में भाग लिया।

दक्षिण एशिया में टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

आरआईएस ने नीतिगत अध्ययनों के लिए दक्षिण एशिया केंद्र (एसएसीईपीएस) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 5 दिसंबर, 2016 को 'दक्षिण एशिया में टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन' पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया के संदर्भ में वृहद आर्थिक प्रदर्शन के उभरते रूझान, आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण, और बाह्य संबंध एवं टिकाऊ आर्थिक विकास से संबंधित आसन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आई, जिस पर दक्षिण एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञों और नीति संबंधी शोधकर्ताओं ने संभावित नीतिगत रूपरेखा पेश करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर खुलकर प्रेरक शैक्षणिक परिचर्चा की।

चित्र में (बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. समन केलेगामा, प्रो. दीपक नैय्यर, डा. पॉश राज पांडेय, डॉ. मुस्त. फिजुर रहमान, और डॉ. सागर परसाई।

वृहद आर्थिक प्रदर्शन के उभरते रूझान, आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण, और बाह्य संबंध एवं टिकाऊ आर्थिक विकास पर चर्चाएं इसके एजेंडे में शामिल थीं। दक्षिण एशिया की ओर से जिन प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया: उनमें शामिल थे प्रो. दीपक नैय्यर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ. मुस्तफिजुर रहमान, कार्यकारी निदेशक, नीतिगत वार्ता के लिए केंद्र, बांग्लादेश; डॉ. समन केलेगामा, कार्यकारी निदेशक, नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका, डॉ. वकार अहमद, उप कार्यकारी निदेशक, टिकाऊ विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान (स्काइप कॉल के माध्यम से); डॉ. पॉश राज पांडेय, अध्यक्ष, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल; डॉ. खोंडाकार गुलाम मोआज्जेम, अतिरिक्त अनुसंधान निदेशक, नीतिगत संवाद के लिए केंद्र (सीपीडी), बांग्लादेश; डॉ. फ्रेडरिको गिल सैंडर, सीनियर कंट्री इकोनॉमिस्ट, विश्व बैंक; डॉ. दिल्ली राज खनाल, संस्थापक अध्यक्ष, नीतिगत अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईपीआरएडी), पूर्व सांसद, नेपाल सरकार; डॉ. नोमान मजीद, रोजगार नीति पर आईएलओ के वरिष्ठ विशेषज्ञ, भारत; डॉ. शेर सिंह वेरिक, उप निदेशक, दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डीडब्ल्यूटी और भारत के लिए कंट्री ऑफिस, श्री विश्वनाथन सुब्रमण्यन, नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, प्रो.एस. के.मोहंती और डॉ.सब्यसाची साहा ने इसमें भाग लिया।

दक्षिण एशिया के विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन की चुनौतियों पर महत्वपूर्ण सबक के साथ यह कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला में विख्यात विशेषज्ञों ने विश्लेषणात्मक साक्ष्यों को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया, जिनके तहत दक्षिण एशिया में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और इससे संबद्ध रोजगार सृजन की राह की विशिष्ट बाधाओं पर प्रकाश डाला गया। भावी दिशाएं तय करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जिनमें मुख्य रूप से मौजूदा बाधाओं से पार पाते हुए और निर्यात आधारित विकास के अवसरों, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तथा व्यापार एवं निवेश में क्षेत्रीय सहयोग से लाभ उठाते हुए तीव्र औद्योगीकरण सुनिश्चित करने के रोडमैप को कवर किया गया।

अमेरिका–भारत व्यापार एजेंडे को नया स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर

आरआईएस ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 15–17 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में 'अमेरिका–भारत व्यापार एजेंडे को नया स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर' विषय पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने 'भारत–अमेरिका व्यापार संबंध' से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर भारतीय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया।

अधिक जानकारी आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है : www.ris.org.in

क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रतिभागीगण ।

हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने संबंधी 'हार्ट ऑफ एशिया' प्रक्रिया के तहत व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश – विश्वास बहाली उपायों (टीसीआई–सीबीएम) के अंतर्गत 3 दिसंबर 2016 को अमृतसर में 'हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी' का आयोजन किया।

'हार्ट ऑफ एशिया' अफगानिस्तान को अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ–साथ सीआईएस देशों से भी जोड़ने की खातिर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। एशिया, ईरान और सीआईएस क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में अफगानिस्तान की जो विशिष्ट सामरिक लोकेशन (अवस्थिति) है उसमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारतीय उद्योगों की साझेदारी में विविधता लाने की अपार क्षमता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और फिक्की के निदेशक श्री गौतम घोष के स्वा्गत भाषणों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। काबुल में भारत के राजदूत मनप्रीत वोहरा ने उद्घाटन भाषण दिया। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. राम उपेंद्र दास ने उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी की मुख्य नीतिगत सिफारिशों में से कुछ ये हैं: पश्चिमी–पूर्वी भारतीय बंदरगाहों और चाबहार के बीच समुद्र–सड़क/रेल मल्टी–मोडल लिंकेज वाणिज्यिक दृष्टि से सुसंगत अथवा लाभप्रद है क्योंकि यह दक्षिण यूरोप (रेल), मध्य एशिया, रूस और उत्तरी यूरोप (रेलवे–सड़क) जाने वाले भारतीय माल (कारगो) का एक संकुलन है। इसे कामयाब बनाने के लिए 'अवधारणा का प्रमाण' हासिल करने की जरूरत है, जिसमें इन तीन कदमों को शामिल किया जा सकता है: थोड़ी सब्सिडी के साथ नियमित रूप से एक शिपिंग सेवा (सप्ताह में एक या दो बार) का संचालन करना, एक मल्टी–मोडल स्थल (प्वाइंट) के रूप में इस बंदरगाह का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए 'सूक्ष्म स्तर' का परिचालन संबंधी अध्ययन कराना और उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर में टीआईआर संधि और कस्टम संबंधी सहूलियत के अन्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करना। दक्षिण और मध्य एशिया को आपस में जोड़ने के लिए सबसे सस्ते एवं सबसे छोटे मार्गों का पता लगाना और उन्हें विकसित करना अत्यंत जरूरी है, जो वास्तव में सड़क मार्ग या भूमि मार्ग (लैंड रूट) होते हैं। इनमें भूमि से घिरे देशों को भूमि से जुड़े देशों में तब्दील करने की क्षमता होती है। इसे लाभप्रद बनाने के लिए ट्रांस–एशियाई राजमार्ग और ट्रांस–एशियाई रेलवे नेटवर्क के रूप में संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के कार्य पर परिचालन के लिहाज से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये रेल–सड़क–समुद्र कनेक्टिविटी के मल्टी–मोडल संदर्भ में उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी के रूप में ऐसी कोई अड़चन ही नहीं होनी चाहिए, जिससे व्यापार और निवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो। अतः व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।

'हार्ट ऑफ एशिया और कनेक्टिविटी' पर संगोष्ठी के दौरान राजदूत मनप्रीत वोहरा उद्घाटन भाषण देते हुए।

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ एक परस्पर संवादात्मक सत्र के लिए 18 नवंबर, 2016 को आरआईएस का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थे: श्री क्रिस्टोफर हैमेल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; श्री माउरीजिओ नवारा, ज्ञान प्रबंधन एवं आउटरीच अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; सुश्री फ्रांसिस्का रैप्पोकसियोलो, वैश्विक भागीदारी अधिकारी, वैश्विक भागीदारी, ज्ञान एवं रणनीति प्रभाग, आईएफएडी, रोम; और सुश्री मीरा मिश्रा, कंट्री कोऑर्डिनेटर, आईएफएडी, भारत।

आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट; और डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट ने प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श में भाग लिया।

एशिया में सेवा व्यापार और नियामकीय सुधारः एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश में

आरआईएस में स्थापित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने टोक्यो स्थित एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) और आईएमआई कोलकाता के सहयोग से कोलकाता में 26–27 अक्टूबर 2016 को 'एशिया में सेवा व्यापार और नियामकीय सुधारः एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश में' नामक विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सेवा व्यापार में मौजूद बाधाओं से संबंधित मुद्दों सहित एशिया में सेवा व्यापार की वर्तमान स्थिति, घरेलू नियमों, नियामकीय ढांचे, सेवा व्यापार से जुड़े सुधारों और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर उनके प्रभाव पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिहाज से एक उत्तम अवसर थी। कार्यशाला में भाग लेने वालों में वरिष्ठ नीति निर्मातागण, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सेवा व्यापार से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के बीस अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। आईएमआई–कोलकाता के निदेशक प्रो. अरिंदम बानिक ने स्वागत भाषण दिया, एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के डिप्टी डीन डॉ. बोकवान यू ने आरंभिक भाषण दिया, आरआईएस में स्थापित एआईसी के प्रोफेसर/समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने भी भाषण दिया और एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के प्रमुख (प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण) डॉ. अलादीन डी. रिल्लो ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। एडीबीआई, आईडीई–जेट्रो, अपेक सचिवालय, नैस्कॉम, आईएमआई कोलकाता, आईसीआरआईईआर, इत्यादि के प्रख्यात विद्वानों और प्रोफेशनल ने विशेष व्याख्यान दिए। डॉ. प्रबीर डे ने 'सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करने एवं व्यापार प्रवाह पर उनके असर' पर एक प्रस्तुति दी और 'सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण मुद्देः डिजिटल सेवाएं एवं ई–कॉमर्स' विषय पर आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. अरिंदम बानिक और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

'एशिया में सेवा व्यापार और नियामकीय सुधार : एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश में' नामक विषय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागीगण।

विकास की उभरती मिसाल के रूप में ब्लू इकोनॉमी

ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) की अवधारणा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। आईओआरए और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आरआईएस ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में काफी सक्रियता के साथ भाग लेता रहा है। संस्थान ने कई प्रकाशन भी प्रस्तुत किए हैं और इसने हाल के महीनों में ब्लू इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न विषयों पर सम्मेलन आयोजित किए।

इस तरह के प्रयासों को जारी रखते हुए आरआईएस ने 29 दिसंबर 2016 को 'विकास की उभरती मिसाल के रूप में ब्लू इकोनॉमी' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रो. वी. एन. अत्री, चेयर, हिंद महासागर अध्ययन, हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए), मॉरीशस विश्वविद्यालय ने विषयगत प्रस्तुति दी। राजदूत राजीव भाटिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की,

'ब्लू इकोनॉमी' पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागीगण।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरंभिक भाषण दिया और आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस. के. मोहंती ने विशेष भाषण दिया। आईडीएसए की सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. रुचिता बेरी ने विशेष परिचर्चा में भाग लिया। इसके बाद आयोजित की गई खुली चर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। समुद्री संसाधनों की बदौलत उत्पादक और टिकाऊ विकास अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सृजित करने की जो भरपूर क्षमता ब्लू इकोनॉमी में निहित है, उसी से यह संभव हो पा रहा है। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर), अक्षय समुद्री ऊर्जा, समुद्री बंदरगाहों एवं शिपिंग और अपतटीय हाइड्रोकार्बन एवं समुद्र तल में मौजूद खनिजों के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं और अवसर हैं।

आरआईएस में इब्सा विजिटिंग फेलोशिप आरंभ

भारत सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के सहयोग से आरआईएस इब्सा डायलॉग फोरम–ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के तहत भारत के अन्य दो भागीदार देशों में प्रत्येक से दो–दो शोध छात्रों (रिसर्च स्कॉलर) को इब्सा विजिटिंग फेलोशिप देगा। यह कार्यक्रम टिकाऊ विकास का समन्वय, समर्थन करने एवं इसे सक्षम बनाने के लिए एक कारगर बहुस्तरीय संस्थागत विकसित करने पर सुसंगत एवं अभिन्न प्रकार से फोकस करता है। यह दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के वैसे शोध छात्रों के लिए उपलब्ध है जिनकी भागीदार देशों में इब्सा डायलॉग प्रक्रिया के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में गहन अनुसंधान करने में गहरी दिलचस्पी है।

आरआईएस ने 28 नवंबर 2016 को इब्सा फेलोशिप का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी की स्वागत टिप्पणियों के साथ आरंभ हुआ।

विदेश मामले मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) सुश्री प्रीति सरन ने कार्यक्रम आरंभ करने

विदेश मामले मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) सुश्री प्रीति सरन आरआईएस इब्सा विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के लांच के अवसर पर उद्घाटन भाषण देती हुईं।

के अवसर पर कहा कि इब्सा को विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक सफल उदाहरण माना गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर तीनों देश बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक डिमरी; भारत में दक्षिण अफ्रीका उच्चायोग के उप उच्चायुक्त श्री बेन जौबर्ट ; एवं भारत में ब्राजील दूतावास की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन सुश्री क्लौडिया विऐरा सैंटोस ने भी इस अवसर पर टिप्पणियां कीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने की।

एसडीजी एवं टिकाऊ विकास के प्रति समेकित दृष्टिकोण

आरआईएस ने 27 से 29 दिसंबर, 2016 को तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन के 99वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर ' एसडीजी एवं टिकाऊ विकास के प्रति समेकित दृष्टिकोण' पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। यह सत्र 28 दिसंबर, 2016 को आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान हाल में अंगीकृत वैश्विक टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की पृष्ठभूमि में टिकाऊ विकास के नए एवं उभरते आयामों और उसके द्व ारा भारतीय मॉडल विकास की चुनौतियों और अवसरों की खोज करने पर विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित मुद्द ों पर गौर किया गया : नया विकास मॉडल–विकास वर्णन में आदर्श बदलाव, विकास की एक समेकित दृष्टि–स्वास्थ्य एवं अन्य एसडीजी, टिकाऊ विकास को मापना एवं औद्योगिकीकरण एवं रोजगार सृजन के

एसडीजी पर आरआईएस विशेष सत्र के प्रतिभागी।

जरिये टिकाऊ आर्थिक विकास। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पुलिन नायक; आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. टी.सी. जेम्स; यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के इकोनोमेट्रिक्स विभाग के प्रमुख प्रो. टी लक्ष्मणसामी; एवं आरआईएस के असिस्टैंट प्रोफेसर डा. सब्यसाची साहा ने इन विषयों पर प्रस्तुतिकरण किए। प्रस्तुतिकरण के बाद अन्य प्रतिभागियों के साथ एक संवादमूलक सत्र आयोजित किया गया।

इंडोनेशिया के विशिष्टमंडल की यात्रा

इंडोनेशिया के एक शिष्टमंडल ने 14 नवंबर, 2016 को आरआईएस संकाय सदस्यों के साथ एक संवादमूलक सत्र के लिए आरआईएस की यात्रा की। राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के विदेश राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग निदेशालय, एसएसटीसी के निदेशक श्री प्रियांतो रोहमतुल्लाह ने इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में : कृषि मंत्रालय के कृषि मानव संसाधन विकास एजेंसी के सीनियर प्लानर श्री डाइडिंग हरदेदी; कृषि मंत्रालय के विदेश सहयोग केंद्र की कोपरेशन मैटेरियल्स कंपोजर श्रीमती हपसारी श्री सुसांति; राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के विकास आवंटन निधियन निदेशालय की युवा प्लानर श्रीमती वुलंदरी; वित मंत्रालय के ऋण एवं अनुदान निदेशालय के श्री इमाम रुसदियांत्रो; एसएसटीसी के जरिये टिकाऊ आर्थिक विकास के कम्युनिकेशन एवं मोनिटरिंग एसोसिएट सिटी अमीनाह स्याहिदाह और आईएफएडी, इंडिया कंट्री रिप्रजेंटेटिव सुश्री राशा उमर शामिल थी।

संवादमूलक सत्र के दौरान इंडोनेशिया के शिष्टमंडल के सदस्य।

आरआईएस की तरफ से महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. राम उपेंद्र दास; विजिटिंग फेलो प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती; विजिटिंग फेलो डा. टी.पी. राजेंद्रन; विजिटिंग फेलो प्रो. टी.सी. जेम्स; रिसर्च एसोसिएट डा. बीना पांडेय एवं सहायक प्रोफेसर डा. सब्यसाची साहा ने विचार विमर्शों में भाग लिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विमुद्रीकरण

आरआईएस ने 15 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विमुद्रीकरण पर एक परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किया। एनआईपीएफपी के निदेशक डा. रथिन रॉय एवं पहले इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य तथा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली के सीनियर फेलो डा. राजीव कुमार इसके सह–अध्यक्ष थे। विचार विमर्श आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषणों के साथ आरंभ हुआ। आरआईएस के सलाहकार श्री सुभोमोनी भट्टाचार्य ने विषयगत प्रस्तुति दी। इसके बाद एक खुली चर्चा आयोजित हुई जिसमें विख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान रूप में विमुद्रीकरण भारत द्वारा अब तक का सबसे गंभीर कदम और सबसे बड़ा सूक्ष्म आर्थिक (माइक्रोइकोनोमिक) कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह विश्वास की एक बड़ी छलांग रही है। इसका अन्य विकासशील देशों के लिए भी काफी महत्व है जिनके लिए इसी प्रकार के सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विमुद्रीकरण पर परामर्श बैठक के प्रतिभागी।

ईआरआईए शिष्टमंडल की यात्रा

अपने अनुसंधान एवं प्रचार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए, आरआईएस दुनिया भर में अपने पार्टनर अनुसंधान संस्थानों के साथ नियमित रूप से वार्ता आयोजित करता है। इनमें कई अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, एसडीजी, विकासशील देशों के बीच सहयोग, विकास सहयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आरआईएस की हमेशा से ही जकार्ता के ईआरआईए के साथ एक विशेष रूप से, भारत की 'पूरब की ओर देखो' नीति पर परस्पर लाभदायक अनुसंधान साझीदारी रही है।

इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, आरआईएस ने 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक के लिए जकार्ता के ईआरआईए से टीम–सदस्यों को आमंत्रित किया। शिष्टमंडल के सदस्यों में सीओओ एवं महानिदेशक श्री इजुरु कोबयाशी; महानिदेशक सुश्री अनीता प्रकाश; वरिष्ठ ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री वेंकटचलम अंबुमोझी; एवं अर्थशास्त्री श्री यासिशी यूएकी शामिल थे। महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; प्रो. एस.के.मोहंती एवं प्रो. राम उपेंद्र दास के नेतृत्व में आरआईएस टीम ने परामर्श बैठक में हिस्सा लिया।

विकासशील देशों के बीच सहयोग पर आईटीईसी/एससीएपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी)/अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रकुल सहायता कार्यक्रम (एससीएपी) के तहत आरआईएस ने 15–25 नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच सहयोग के बारे में शिक्षा पर एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को विकासशील देशों के बीच सहयोग (एसएससी) की व्यापक अवधारणा, विशेष रूप से वैश्विक सहायता ढांचे में देखे जा रहे व्यापक बदलावों के बाद विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में जारी पुनरुत्थान के परिप्रेक्ष्य में विकास सहयोग के बारे में परिचित कराना था। बैठक में अन्य बातों के अलावा संबंधित देशों की एकल उपलब्धियों के आधार पर एसएससी के औचित्य, अवधारणा एवं रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके जरिये उन्हें एसएससी से होने वाले लाभों एवं उनकी सामूहिक भागीदारी के मार्ग की बाधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सिद्धातों, नीतियों, तौर–तरीकों (जिनमें राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वामित्व, स्वतंत्रता, समानता, गैर–शर्त, गैर–हस्तक्षेप एवं आपसी लाभ शामिल हैं) और प्रचलनों पर गौर किया गया जो पूरे एसएससी के दौरान स्पष्ट थी और साथ ही, इस पर भी गौर किया गया कि किस प्रकार नीतिगत झुकावों और एसएससी की ताकतों को व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की गई कि किस प्रकार एसएससी विकसित–विकासशील देशों के सहयोग (एनएससी) से एक अलग प्रतिमान है और किस प्रकार एसएससी को एक स्वैच्छिक साझीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो अब राजनीतिक एकजुटता की प्रारंभिक बुनियादों से ऊपर उठ कर एक अधिक परिपक्व मंच में विकसित हो गया था न कि किसी के रूप में एनएससी के एक स्थानापन्न के रूप में।

एसएससी/एनएससी इस कार्य में विभिन्न देशों से आये 28 प्रतिनिधियों ने वा अन्य मंत्रालयों, विदेश मामले/वित्त/वाणिज्य अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिविल सोसाइटी से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे लोगों ने भाग लिया। बौद्धिक सत्रों के अतिरिक्त, एक अध्ययन दौरे का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को समूह चर्चाओं एवं प्रस्तुतिकरणों के माध्यम से उनके अध्ययन परिणामों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

आरआईएस संकाय के साथ आईटीईसी कार्यक्रम के प्रतिभागी।

ब्रिक्स समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित...
पेज 2 से जारी

प्रभुत्वशाली ताकतों के रूप में उभर रहे हैं। आज ब्रिक्स की अनदेखी दरअसल इतिहास में नजर आ रहे बदलावों की अनदेखी है।' उन्होंने वैश्विक एजेंडे और नई विश्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने में ब्रिक्स सिविल फोरम की विशेष अहमियत पर भी प्रकाश डाला। डॉ. थरूर ने यह भी कहा कि मौजूदा प्रणाली को या तो हमारे लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए अथवा पतन के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिक्स में सिविल सोसायटी की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सोसायटी अपने विचारों में सामंजस्य सुनिश्चित करके और इनके बारे में सरकार को सूचित करके शिखर सम्मेलन के एजेंडे को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ब्रिक्स देशों ने पहले ही 'नव विकास बैंक' को बाकायदा अस्तित्व में ला दिया है और अब भी उनके बीच ज्ञान केंद्र (हब) बनाने की सख्त जरूरत है क्योंकि यह भूमंडलीकृत, आपस में जुड़ी हुई एवं नेटवर्क के जरिए संचालित होने वाली दुनिया की अत्यंत जरूरी आवश्यकता है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) श्री अमर सिन्हा ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि विचार–विमर्श से सरकार के ज्ञान का संवर्धन होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह दलील दोहराई कि ब्रिक्स नए विचारों का एक फोरम है जो वैश्विक वृत्तांत को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने बिम्सटेक देशों को आमंत्रित किया है और वह यह जानना चाहता है कि वे नए वैश्विक एजेंडे के संबंध में ब्रिक्स देशों से क्या उम्मीद रखते हैं।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश सुपर पावर नहीं हैं, लेकिन वे विश्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। यही देश फैसला करेंगे कि नई संस्थागत व्यववस्था का स्वरूप क्या होगा और इस नई व्यवस्था के बारे में तब तक निर्णय नहीं लिया

जा सकता जब तक कि सरकार के कदमों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का समर्थन हासिल न हो जाए। सरकार अवश्य ही बेहतर कर सकती है, बशर्ते कि यह सिविल सोसायटी के जरिए लोगों से संवाद करना शुरू कर दे।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में विशेष जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स पूर्व लगभग 100 आयोजनों में ब्रिक्स के सदस्य देशों की ओर से सर्वाधिक मौजूदगी सिविल फोरम में ही दर्ज की गई थी और यह सिविल सोसायटीज की भागीदारी की बदौलत ही संभव हो पाई थी। उन्होंने कहा कि सिविल सोसायटी में ही सभी सक्रिय लोगों अथवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अनूठी क्षमता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में एफआईडीसी ही वह महत्वपूर्ण जरिया है जो विकास सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत विकसित हुआ है। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए), शिक्षाविदों और सिविल सोसायटी संगठनों की एक त्रिपक्षीय पहल है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एवं एफआईडीसी की अध्यक्ष अनुराधा चिनॉय ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स के बहुपक्षीय मॉडल में वैश्विक गवर्नेंस को बदलने की क्षमता है। ब्रिक्स, सिविल सोसायटी के लिए खुला है और सिविल सोसायटी वैश्विक शक्तियों की सर्वोच्चता को ध्वस्त करने, मानवीय सहायता, आपसी लाभ, बहु–ध्रुवीय प्रणाली, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, समावेशी विकास, बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद के लिए ब्रिक्स को अपनी ओर से सक्रिय सहयोग देती है।

अधिक जानकारी आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है : www.ris.org.in

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- पोषण के लिए कृषि एवं खाद्य प्रणालियों पर वैश्विक पैनल के साथ 6 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान (पीएचएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पोषण एवं विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व (सैपलिंग) के शुभारंभ में भाग लिया।
- 15–16 अक्टूबर, 2016 को ढाका में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, बांग्लादेश, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), भारत, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल, टिकाऊ विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान एवं श्रीलंका का नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नौवें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन (एसएईएस–9), '2030 में दक्षिण एशिया की पुनर्कल्पना', में 'दक्षिण एशिया में एक समावेशी, न्यायोचित एवं शांतिपूर्ण समाज की दिशा में कौन हैं बदलाव के कारक' सत्र की अध्यक्षता की।
- 22 अक्टूबर 2016 को उदयपुर में आयोजित सेवा मंदिर की अर्ध वार्षिक कार्यकारी परिषद बैठक में भाग लिया।
- संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, चाइनीज एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनोमिक कॉपरेशन (सीएआईटीईसी), नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (एनईएस्टी) द्वारा 7 नवंबर 2016 को बीजिंग में संयुक्त रूप से आयोजित विकासशील देश के बीच सहयोग प्रदाता एवं एसडीजी 17 : टिकाऊ विकास लक्ष्यो, उपलब्धियों को आगेबढ़ाने पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में ' एसएससी एवं अन्य देशों की तुलना में इसका अनूठापन' पर सत्र में पैनलिस्ट।
- संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, चाइनीज एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनोमिक कॉपरेशन (सीएआईटीईसी), नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (एनईएस्टी) द्वारा 8 नवंबर, 2016 को बीजिंग में संयुक्त रूप से आयोजित विकासशील देश के बीच सहयोग प्रदाता एवं एसडीजी 17 : टिकाऊ विकास लक्ष्यो, उपलब्धियों को आगे बढ़ाने पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'एसएससी की प्रभावशीलता, एमएंडई एवं उसके मॉडलों से तुलना पर प्रस्तुति दी।
- 13 नवंबर 2016 को भोपाल में प्रज्ञा प्रवाह एवं भारत भवन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रथम वार्षिक लोकमंथन 2016 में 'भारत, भू–राजनीति एवं वैश्विक परिदृश्य' पर एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया।
- असम विधानसभा द्वारा 22 नवंबर 2016 को गुवाहाटी में आयोजित अनुकूलन कार्यक्रमों में 'टिकाऊ विकास लक्ष्यो' पर प्रस्तुति दी।
- जापान इकोनोमिक फाउंडेशन (जेईएफ) एवं केंद्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान (सीआईईएम) द्वारा 24 नवंबर 2016 को हनोई में संयुक्त रूप से आयोजित भारत प्रशांत फोरम में 'व्यापार को घरेलू नीति सुधारों के साथ जोड़ना : आर्थिक विकास की दिशा में समन्वित कदम के लिए सर्वसहमति का निर्माण' पर एक सत्र में परिचर्चा में भाग लिया।
- एनईएसटी, एसएआईआईए, आरआईएस एवं शियामेन विश्वविद्यालय द्वारा 30 नवंबर 2016 को नैरोबी में संयुक्त रूप से आयोजित जीपीईडीसी के एचएलएम2 के दौरान '2030 कार्यसूची के तहत विकास सहयोग के लिए प्रयास एवं जवाबदेही: अभिसरण की दिशा में कदम' पर आयोजित कार्यशाला में 'अभिसरण या सुस्पष्ट विशेषता : विकासशील देश के बीच सहयोग के केस अध्ययनों और वैचारिक रुझानों से प्रमुख सीख' पर प्रस्तुति दी।
- जर्मन डेवेलपमेंट इंस्टीच्युट, ड्यूश इंस्टीच्युट फॉर इंटविकलुंग्सपोलिटिक (डीआईई) एवं साउथ अफ्रीकन इंस्टीच्युट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एसएआईआईए) दक्षिण अफ्रीका द्वारा 30 नवंबर 2016 को संयुक्त रूप से आयोजित 2030 एजेंडा के लिए कारगर विकास सहयोग के लिए जवाबदेही : आगे कैसे बढ़ें' विषय पर एक सत्र में परिचर्चा में भाग लिया।

- 30 नवंबर 2016 को नैरोबी में केन्याइ सरकार, मलावी सरकार, एयू–एनईपीएडी, रियल्टी ऑफ ऐड नेटवर्क के सहयोग से एनईएसटी अफ्रीका द्वारा आयोजित 'अफ्रीका के विकास के लिए विकासशील देशों के बीच साझीदारी–जबावदेही को बेहतर बनाना' पर सम्मेलन में परिचर्चा में भाग लिया।
- 7 दिसंबर 2016 को मुंबई में भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित ब्रिक्स अंतः बैंक सहयोग तंत्र : उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक रेटिंग एजेन्सियों की स्थापना की व्यावहार्यता खोजने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलेंटरी एक्शन तथा वादा ना तोडो (डब्ल्यूएनटीए) द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में 'टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) को समर्थन एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक में' पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग–ब्रिक्स परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस.के मोहंती

- 10–14 अक्तूबर 2016 को जकार्ता में आयोजित हिंद महासागर रिम एकेडेमिक समूह की 22वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
- 12 अक्तूबर 2016 को जकार्ता में आयोजित हिंद महासागर रिम एकेडेमिक समूह की 22वीं बैठक में 'आईओआरए में मछली पालन के आर्थिक आयाम' पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित गोल मेज वार्ता 'राष्ट्रकुलः व्यापार एवं आर्थिक अवसर' में परिचर्चा में भाग लिया।
- 24 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में आयोजित भारत–मर्कोसुर पीटीए विस्तार पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 30, नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में आयोजित ईरान, बांग्ला देश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के साथ भारत के द्वि पक्षीय व्यापार संबंधों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 5 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में भारतीय निर्यात–आयात बैक द्वारा भारत में निर्यात एवं रोजगार के बीच अंतःसंपर्कों पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- 6 दिसंबर, 2016 को सामुद्रिक अर्थव्यवस्था पर फिक्की कार्य बल समिति द्वारा आयोजित सामुद्रिक अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों पर परिचर्चा में भाग लिया
- 8 दिसंबर, 2016 को भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा एक्जिम बैंक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान वार्षिक (आईआरए) पुरस्कार समिति के लिए जूरी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया।
- 9 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग में आयोजित ईरान, बांग्ला देश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 13 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझीदारी समझौता (सीईसीपीए) वार्ताओं एवं भारत–इजरायल एफटीए वार्ताओं पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 19 दिसंबर 2016 को पुणे में सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय विद्यालय द्वारा सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारत एवं हिन्द महासागर पर चौथे अंतरराष्ट्रीय संबंध सम्मेलन : सततता, सुरक्षा एवं विकास में 'सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के लिए एक रूपरेखा : टिकाऊ सामुद्रिक सहयोग की दिशा में दृष्टिकोण' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- 1 अक्तूबर 2016 को भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल द्वारा केपीएमजी एवं सी–डीईपी, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 'ईयू–भारत डिजिटल एजेंडा : 2020 को मजबूत बनाना : व्यापार प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन' पर एक कार्यशाला में हुई परिचर्चा में भाग लिया।
- 3 अक्तूबर 2016 को विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'डब्ल्यूटीओ, पीटीए एवं विकासशील देशों पर आसियान राजनयिकों के लिए 10वें विशेष कोर्स को संबोधित किया।
- 5 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास' पर निर्यात समिति की 22वीं बैठक में भाग लिया।
- 7–8 अक्तूबर 2016 को अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) एवं स्नातक अध्ययन तथा कृषि में अनुसंधान के लिए दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्रीय केंद्र (एसईएआरसीए), लॉस बनोस, लुगना, फिलीपींस द्वारा 'आसियान क्षेत्र में कृषि रूपांतरण एवं बाजार समेकनः खाद्य सुरक्षा एवं समावेशन चिंताओं का प्रत्युत्तर' विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में परिचर्चा में भाग लिया।
- 17 अक्तूबर, 2016 को नई दिल्ली में उद्योग चैंबर पीएचडी द्वारा आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाएं' पर एक संगोष्ठी में एक शिष्टमंडल को संबोधित किया।
- 25 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 'नैरोबी घोषणापत्र : क्या भारत अपने कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा कर सका ?' पर 2004–2008 बैच के

प्रो. राम उपेंद्र दास 30 नवंबर–2 दिसंबर, 2016 को जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीच्युट, बर्लिन, जर्मनी एवं ड्यूशेज इंस्टीच्युट फॉर एंटविकलुंग्सपॉलिटिक द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय किक ऑफ सम्मेलन' थिंक 20 (टी20) में बोलते हुए

भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के उप सचिव स्तर के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक परिचर्चा में भाग लिया।

- 25 अक्तूबर 2016 को कोनरैड –एडेनायूर – स्टिफटंग, गुड़गांव, हरियाणा के साथ टेरी द्वारा आयोजित 'संसाधन सुरक्षा : वैश्विक व्यापार एवं निवेश संरचना में घरेलू हितों के प्रासंगीकरण' पर एक संसाधन वार्ता में भाग लिया तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं ब्रिक्स के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों–भूमिका का लाभ उठाने पर पत्र प्रस्तुति दी।
- 12 नवंबर 2016 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'व्यापार मुद्दे एवं भूमंडलीकरणः डब्ल्यूटीओ एवं क्षेत्रीय व्यापार गुट' पर एडवांस्ड लीडरशिप कार्यक्रम को संबोधित किया।
- 22 नवंबर 2016 को ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी), गुड़गांव, हरियाणा द्वारा आयोजित 'व्यापार एवं टिकाऊ विकास : विकासशील देशों के बीच एवं क्षेत्रीय सहयोग' पर सम्मेलन के आईटीईसी प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- 28 नवंबर 2016 को भारतीय इंजीनियरिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ' भारत का विजन 2030–इंजीनियरिंग एवं तकनीकविद् क्या कर सकते हैं ?' पर 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में परिचर्चा में भाग लिया।
- 30 नवंबर–2 दिसंबर 2016 को ड्यूशेज इंस्टीच्युट फॉर एंटविकलुंग्सपॉलिटिक एवं जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीच्युट, बर्लिन, जर्मनी द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय किक ऑफ सम्मेलन' थिंक 20 (टी20) में परिचर्चा में भाग लिया।
- 7 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में पीएचडी उद्योग चैंबर द्वारा आयोजित ' दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार–अवसर एवं चुनौतियों' पर एक क्रेता–विक्रेता बैठक में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 9 दिसंबर, 2016 को एमिटी स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उ.प्र. की विभागीय शोधकर्ता समिति (डीआरसी) के सदस्य के रूप में मनोनित हुई।

प्रो. टी.सी.जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 4 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा आयोजित 'एमएसएमई के लिए आईपीआर पर संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमएसएमई के लिए भौगोलिक संकेतकों के महत्व पर एक व्याख्यान दिया।
- 7 एवं 8 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में इग्नू विशेषज्ञ समिति की बैठकों में पीजी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए एक सदस्य के रूप में भागीदारी की।
- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में 'पारंपरिक बैंडों की सुरक्षा के लिए एक माध्यम के रूप में भौगोलिक संकेतक' विषय पर महिला उद्यमियों के परिसंघ द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सम्मेलन को संबोधित किया।
- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान में कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकारों की समझ पर एक सप्ताह चलने वाले राष्ट्रीय कार्यशाला में 'कॉपीराइट में विशिष्ट आर्थिक अधिकारों' पर व्याख्यान दिया। 24 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एनएफआई), एलाइव एंड थ्राइव (ए एंड टी) एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव (एमआई) के साथ मिल कर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सहयोग, भारत (सीएफएनएस) द्वारा 'एसडीजी एवं डब्ल्यूएचए के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण लक्ष्यों को अर्जित करने पर प्रतिबद्धता एवं कदम ' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में एक संयुक्त सिविल सोसाइटी घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया जिसमें महिलाओं की अगुवाई में भारत को रूपांतरित करने के लिए एक ' सतत पोषण क्रांति' की अपील की गई।
- 11 दिसंबर 2016 को जमीनी स्तर के वकीलों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, अहमदाबाद एवं एनएलयू, दिल्ली में सेंटर फॉर इनोवेशन, आईपी एवं कंपटीशन लॉ द्वारा भारत की पारंपरिक ज्ञान सुरक्षा व्यवस्था पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में ' पारंपरिक ज्ञान का पैटेंटीकारण : दुरुपयोग के खिलाफ रक्षात्मक एवं आक्रात्मक सुरक्षा' पर प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आईपीआर चेयर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ' ट्रिप्स एवं उभरता परिदृश्य : ट्रिप्स एवं मुद्दों का एक दशक' सत्र की अध्यक्षता की।

डा. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 1–2 दिसंबर 2016 को पेरिस में एएफडी द्वारा आयोजित 'कॉमंस एंड डेवलपमेंट विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ' जर्मप्लाज्म एवं कॉमंस : फ्रॉम ग्लोबल टू द फील्ड' पर प्रस्तुति दी।
- 29–30 नवंबर 2016 को ओईसीडी एसटीआई नीति प्रभाग एवं यूनेस्को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति प्रभाग, पेरिस में आयोजित चर्चा बैठकों में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दास

रिसर्च एसोसिएट

- 15–16 अक्तूबर 2016 को ढाका, बांग्ला देश में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) द्वारा आयोजित 9वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन में 'दक्षिण एशिया में विकास का वित्तपोषणः पारंपरिक दृष्टिकोणों से आगे' में प्रस्तुति दी।
- 27 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित 'स्वर्ण नीति–विजन 2020' पर गोल मेज चर्चा पर भाग लिया।

डा. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 21 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटैबिलिटी (सीबीजीए) एवं फाइनेंशियल ट्रांसपैरेसी कोलिशन द्वारा आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं वित्तीय पारदर्शिता में सुधार : एशिया के लिए एक क्षेत्रीय एजेंडा की दिशा में ' पर आयोजित कार्यशाला परिचर्चा में भाग लिया।

नवीनतम प्रकाशन

रिपोर्ट्स

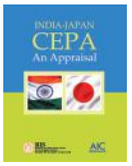

भारत और टिकाऊ विकास लक्ष्य : भविश्य का रास्ता (इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स : द वे फॉरवर्ड)
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

इंडिया–जापान सेपा : ऐन अप्रेजल
वी.एस.शेषाद्री
आरआईएस एंड एआईसी, नई दिल्ली, 2016

इब्सा : ट्रिनिटी फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रैसी एंड सस्टेनेबिलिटी
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

बिम्सटेक : द रोड अहेड
आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

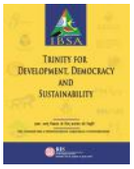

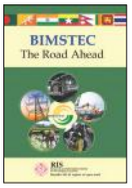

आरआईएस परिचर्चा प्रपत्र

#207 : *ट्रेड इन हाई टेक्नोलॉजी प्रॉडक्ट्स ट्रेंड्स एंड पॉलिसी इम्परेटिव्स फॉर ब्रिक्स*, सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा एवं प्रातिव शॉ

#206 : *इंडिया–अफ्रीका सीड सेक्टर कोलैबोरेशंस : इमर्जिंग प्रॉस्पेक्ट्स एवं चैलेंजेज*, टी.पी.राजेंद्रन एवं अमित कुमार

#205 : *द ब्रिक्स इनिशिएटिव : टूवार्ड्स ए न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चरः ए असेस्मेंट विद सम प्रपोजल्स*, सुनंदा सेन

आरआईएस नीति सार

#76 *फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी डिलिवरी फॉर एसडीजी : अवे फॉरवर्ड फॉर टीएफएम*, सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा, नवंबर, 2016

ब्लू इकोनोमाई नीति सार

फिशरीज सेक्टर इन आईओआरए : ड्राइविंग फोर्स इन रीजन'स ब्लू इकोनोमी, एस.के.मोहंती, प्रियदर्शी दास एवं आस्था गुप्ता, आरआईएस, नई दिल्ली

एफआईडीसी नीति सार

#9: *टू एएसडी : साउदरनाइजेान ऑफ ओडीए*, सचिन चतुर्वेदी मिलिन्दो चक्रबर्ती, हेमंत शिवा, नवंबर 2016

एफआईडीसी परिचर्चा प्रपत्र

#2 *इनबाउंड इंटरनेशनल स्टुडेंट मोबिलिटी इन इंडिया : पाथ टू अचीवेबल सक्सेस*, विद्या राजीव येरावदेकर

जर्नल

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा
अंक 18 संख्या 2, जुलाई, 2016

आरआईएस डायरी

अंक 12 संख्या 4, अक्तूबर, 2016

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. ' आर्थिक कूटनीति में सयाना होता देश'. *इंडिया टूडे* (हिन्दी वर्षगांठ संस्करण), 30 नवंबर, पीपी 73–75।

दास, राम उपेंद्र. 2016. 'हाऊ टू टेक रशिया–इंडिया इकोनोमिक्स टाइज टू नेक्स्ट लेवल' *रशिया डायरेक्ट.* 15 अक्तूबर.

डे, प्रबीर एवं मुस्ताफिजुर रहमान (संपादक). 2016. रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया : एस्सेज इन ऑनर ऑफ डा. एम. रहमतुल्लाह. नॉलेज वर्ल्ड. नई दिल्ली.

डे, प्रबीर एवं मुस्ताफिजुर रहमान (संपादकीय). 2016. सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंड : न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप, नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली.

डे, प्रबीर. 2016. डे, प्रबीर एवं मुस्ताफिजुर रहमान (संपादक). में 'बीबीआईएन एमवीएः गुड बिगनिंग बट मेनी चैलेंजेज'। रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया : एस्सेज इन ऑनर ऑफ डा. एम. रहमतुल्लाह. नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली.

डे प्रबीर. 2016. डे, प्रबीर एवं सुतिफंड चिराथिवत (संपादक) में 'लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट : कनेक्टिविटी चैलेंजेज इन इंडिया'ज नॉर्थ ईस्ट'. सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंडः न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप. नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली.

कुमारस्वामी, दुरैराज एवं इमदादुल इस्लाम हल्दर. 2016. डे, प्रबीर एवं सुतिफंड चिराथिवत (संपादक में ' ट्रेड इन सर्विसेज इन एशिया पैसिफिक। असेसिंग बैरियर्स एंड इंप्लीकेशंस फॉर सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन इन इंडिया ', सेलेब्रेटिंग द थर्ड डिकेड एंड बियोंड : न्यू चैलेंजेज टू आसियान–इंडिया इकोनोमिक पार्टनरशिप. नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली.

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाष: 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74 ई–मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia
@RIS_NewDelhi
www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश कुमार मल्होत्रा